



Neutral Citation No - 2026:AHC:168781

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-

7645 / 2026

अनस और 2 अन्य

..... आवेदक (गण)

बनाम

प्रधान सचिव (गृह) के जरिए उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

..... प्रतिवादी (गण)

आवेदक (गण) के लिए अधिवक्ता : अतुल कुमार

प्रतिवादी (गण) के लिए अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता को राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह वर्तमान आवेदन आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 69 वर्ष 2026, धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(1) के अन्तर्गत, थाना शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर में पंजीकृत प्रकरण में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की जाए।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष हैं और इस प्रकरण में उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। उनका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदकों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आगे यह कहा जाता है कि शुरू में

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एफआईआर धारा 61 (2), 325 भारतीय न्याय संहिता, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 (1) (एल), शस्त्र अधिनियम की धारा 3/4/25 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत दर्ज की गई थी। यह आगे कहा जाता है कि पहले आवेदकों को पुलिस द्वारा 21.3.2026 को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा वाद अपराध संख्या 69/2026 के वाद में, धारा 61(2), 325 भारतीय न्याय संहिता, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(एल), शस्त्र अधिनियम की धारा 3/4/25 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत दिनांक 30.3.2026 के आदेश द्वारा रिहा कर दिया गया था। आवेदक नौ दिनों से अधिक समय तक जेल में रहे। जेल से रिहा होने के बाद जांच अधिकारी द्वारा गोवध निवारण अधिनियम, 1955 की धारा 3/5/8 जोड़ी गई और धारा 11(1)(1) (1) को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1) (1) में बदल दिया गया है और अब जांच अधिकारी उसी अभियोग के अपराध में आवेदकों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उन्हें संबंधित विद्वान अदालत द्वारा जमानत दे दी गई है। यह आगे कहा गया है कि सह-आरोपी ताहिर को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 7305/2026 में दिनांक 6.8.2026 के आदेश के माध्यम से अग्रिम जमानत दी गई है। आवेदकों के पास कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। अब धारा 3/5/8 भारतीय न्याय संहिता जोड़ी गई है और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1) (एल) को धारा 11(1)(1) में बदल दिया गया है, पुलिस अतिरिक्त धारा के तहत आवेदकों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **भद्रेश बिपिनभाई सेठ बनाम गुजरात राज्य और और अन्य 2016(1) एससीसी (सीआरआई) 240** में शीर्ष न्यायालय के निर्णयों पर बहुत भरोसा किया है और **मनोज सुरेश जाधव और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2018 एससीसी ऑनलाइन एससी 3428**, जिसमें आवेदक को सीआरपीसी की धारा 439 के तहत नियमित जमानत पर रिहा किये जाने के बाद धारा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



438 सीआरपीसी के तहत अतिरिक्त धाराओं में अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने भी **आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 9742/2021 की धारा 438 सीआरपीसी** के तहत पारित इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें आरोपी को नियमित जमानत दिए जाने के बाद अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था। **उन्होंने आगे कहा है कि आवेदक के पास कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है।** आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक जांच और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच एजेंसी या संबंधित न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि, यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, जांच में सहयोग करेगा, और न्यायालय द्वारा लगाई जा सकने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है, हालांकि, वह तथ्यात्मक पहलू पर विवाद नहीं करता है।

6. मैंने दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं और अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. **सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और अन्य, (2020)**

5 एससीसी 1 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अग्रिम जमानत देने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, जांच के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की संभावना, या गवाहों को डराने सहित सबूतों के साथ छेड़छाड़, न्याय से भागने की संभावना, जैसे कि देश छोड़ना आदि पर विचार करना होगा। आगे यह माना गया है कि न्यायालयों को आम तौर पर अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक को जिम्मेदार ठहराया गया भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे विचारों से निर्देशित किया जाना चाहिए, जबकि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि अग्रिम जमानत दी जाए या इसे अस्वीकार किया जाए। अनुदान देना है या नहीं देना यह विवेक का विषय है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय के वाद 676 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक जनादेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जांच के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है जब हिरासत में जांच आवश्यक हो जाती है या यह एक जघन्य अपराध है या जहां गवाहों या अभियुक्त को प्रभावित करने की संभावना होती है, वह फरार हो सकता है। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह वैध है, यह अनिवार्य नहीं है कि गिरफ्तारी की जानी चाहिए। गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व और इसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी को नियमित बना दिया जाता है, तो यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपूरणीय नुकसान पहुंचा सकता है। यदि जांच अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा या समन की अवहेलना करेगा और वास्तव में, जांच में सहयोग करता है तो अधिकारी पर आरोपी को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

9. अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ, आरोप की प्रकृति, आवेदकों की भूमिका और वाद के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत के लिए एक वाद बनाया जाता है।

10. तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन को निम्नलिखित निर्देशों के साथ अनुमति दी जाती है: -

(i) उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदकों-अनस, असद और शाकिब की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें संबंधित पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान राशि के दो जमानतों के साथ 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने पर मुकदमे के समापन तक अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) आवेदक जांच के दौरान जांच अधिकारी के साथ सहयोग करेंगे और जांच करने के उद्देश्य से जब भी आवश्यक हो, जांच अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे;

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

11. किसी भी शर्त के चूक या दुरुपयोग में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता संबंधित अदालत के समक्ष आवेदकों को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

12 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”